सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का उन्नयन

साभार: लाइव मिंट
(18 नवंबर, 2017)

अंजेला तनेजा
(निदेशक, शिक्षा, केअर इंडिया)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

यहाँ समर्थन के लिए निजी क्षेत्रों पर आश्रित होने के बजाय, भारत की आर्थिक क्षमता को साकार करने पर ध्यान देना चाहिए।

विश्व बैंक की हाल ही में फ्लैगशिप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2018 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सन्दर्भ में कुछ तत्काल चुनौतियों को संबोधित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक डेवलपमेंट रिपोर्ट में शिक्षा का जिक्र किया है। निजी स्कूलों में नामांकन का बढ़ाना एक वैश्विक प्रवृत्ति है और इस घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और साथ ही इसके साक्ष्य पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

कई देशों में शिक्षा प्रणाली अपेक्षा के अनुरूप नहीं चल रही है और कई परिवार निजी स्कूलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है, खासकर तब, जब सार्वजनिक विद्यालय स्वयं पूरी तरह से मुक्त नहीं है। भारत भी मुफ्त माध्यमिक सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में समान पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के सीखने के परिणामों में 40 देशों के शोध में कोई फर्क नहीं पड़े हैं। निजी विद्यालय बेहतर प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत लाभ वाले पृष्ठभूमि वाले बच्चों का नामांकन करते हैं जो इसलिए नहीं कि वे बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भुगतान करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत में एक लोकप्रिय धारणा को चुनौती देती है और इसमें कोई सुसंगत प्रमाण नहीं पाया जाता है कि निजी स्कूल सार्वजनिक स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं। दरअसल, भारत में शिक्षा के 1. 27 मिलियन अप्रशिक्षित शिक्षकों में, 925,000 निजी स्कूलों में हैं, जो कि गुणवत्ता के सन्दर्भ में उपेक्षा है। राज्यों की क्षमता पूरी तरह से मॉनिटर करने और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने, नकारात्मक इक्विटी प्रभाव के खिलाफ कम करने और अनुबंध अनुपालन को बढ़ाया जाना चाहिए।

इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि कुछ निजी स्कूलों के लिए लाभ की तलाश उन्हें नीति विकल्पों की वकालत करने का नेतृत्व कर सकती है जो छात्रों के हितों में नहीं है। कुछ उदाहरण के रूप में, निजी स्कूल वास्तव में निचले इनपुट लागतों के साथ तुलनीय सीखने के परिणाम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह काफी हद तक कम शिक्षक वेतन के माध्यम से प्राप्त होता है। रिपोर्ट ने दोहराया कि यह शिक्षा को सस्ता तो बना सकता है, लेकिन यह इसे बेहतर नहीं बना सकता और समय के साथ योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को कम करने का अतिरिक्त नुकसान होता है। यदि बच्चों को सीखने के लिए स्कूल में आने के लिए कदम उठाए जाते हैं, शिक्षकों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए कौशल और प्रेरणा मिलती है, कक्षाएं और प्रबंधन तक पहुंच को आसन बनाया जाता है और स्कूलों में गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अन्य शोध, जैसे ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट, सुझाव देती है कि सीखने के परिणाम दोनों स्थिति में खराब हैं।

वहां भी स्पष्ट जोखिम हैं, क्योंकि निजी विद्यालय उच्च-आय वाले छात्रों को छोड़ देते हैं जो सिखाने के लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था के भीतर सबसे अधिक वंचित रहते हैं। निजी स्कूलों पर निर्भरता परिवार की आय पर शिक्षा प्रणाली को अलग करती है और मौजूदा सामाजिक दरारों को मजबूत करती है; यह लंबे समय में प्रभावी सार्वजनिक स्कूली शिक्षा के लिए राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र को भी कमजोर करता है। भारत में यह विशेष रूप से खतरनाक परिणाम है जहां जाति, लिंग और कक्षा असमानताओं का वर्चस्व है। दरअसल, भारत में हालिया शोध से पता चलता है कि भले ही यह सरकारी स्कूलों में कम हो रहा हो, लेकिन निजी नामांकन में जेंडर के आधार पर असमानताएं बढ़ रही है। अपेक्षाकृत अमीर देशों के लिए डेटा यह दर्शाता है कि कम स्तर के प्रतिस्पर्धा वाले सिस्टम में उच्च सामाजिक समावेश है और सरकारी सिस्टम में ऊपर की ओर गतिशील सामाजिक गतिशीलता अधिक है।

इस सबूत के बावजूद, और सभी के लिए गुणवत्ता की शिक्षा देने की चुनौती के पैमाने को देखते हुए, सरकारें समर्थन के लिए उत्तरदायी रूप से निजी क्षेत्र की ओर देख रही हैं। हालांकि, निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को ट्रैक करने के लिए तंत्र विकसित किए गए हैं, यहां तक कि विकसित देशों में भी इसे कमजोर या अनुपस्थित माना जाता है। इस विनियामक क्षमता का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और मानव संसाधन निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निजी विद्यालयों की देखरेख गुणवत्ता स्कूली शिक्षा प्रदान करने से अधिक आसान नहीं हो सकता है और ष्सरकारों को एक समान संग्रह वाले विनियमन के मुकाबले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे और अधिक सरल बनाया जा सकता है।ष

भारत ने निजी स्कूलों के लिए विनियामक चौखटे विकसित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कई राज्यों ने शुल्क-विनियमन कानून बनाने और निजी क्षेत्र की असफलताओं को चुनौती देने के लिए हस्तक्षेप करने वाले अदालतों को शामिल किया है। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को स्कूलों में सुरक्षा पर दिशानिर्देश लागू करने के लिए हस्तक्षेप किया; जनवरी में इसे शुल्क विनियमन लागू करना पड़ा विनियामक क्षमताओं का निर्माण, हालांकि केवल एक ही समाधान है। दीर्घकालिक समाधान इसकी जटिलता में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने में है कि भारत के सभी बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है।

सरकार ने दिसंबर, 2017 में 25 वर्षों में पहली नई शिक्षा नीति का अनावरण किया है। यहाँ महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने की जरूरत है और गुणवत्ता में इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें भारत के सभी देशों के लिए स्वतंत्र, गुणवत्ता, न्यायसंगत और सुरक्षित सार्वजनिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल हो। जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करके वैश्विक नेतृत्व में भारत की आकांक्षाओं को हासिल करने में मदद करेगा। यह पर्याप्त संसाधनों द्वारा समर्थित होना चाहिए। भारत सकल घरेलू उत्पाद के लिए शिक्षा के 6% आवंटन के वैश्विक और घरेलू बेंचमार्क के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन 4% सीमा को पार नहीं किया है। गरीबों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में निवेश करने में विफल होना, भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं को और विस्तृत करेगा। देखा जाये तो सुधार की राह चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन निष्क्रियता की लागत बहुत अधिक होगी।

वर्ल्ड डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2018

रिपोर्ट का उद्देश्य

- विश्व बैंक की 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस' (LEARNING to Realize Education's Promise) शिक्षा पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से चार विषयों पर गंभीरता से विचार करती है:
- शिक्षा का वादा।
- 'सीखने की प्रक्रिया' पर अधिक जोर।
- कैसे स्कूलों में 'सीखने की प्रक्रिया' को बढ़ावा मिले?
- कैसे व्यवस्था को 'सीखने की प्रक्रिया' के अनुकूल बनाया जाए?

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल सामान्य रूप से शिक्षा पर चर्चा नहीं की गई है बल्कि कुपोषण और गरीबी से शिक्षा के अंतर्संबंध एवं इसके निजीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों युवाओं को जीवन में बेहतर करने का मौका इसलिये नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उन्हें जीवन में सफल होने के लिये आवश्यक शिक्षा देने में नाकाम रहते हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि कम-आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर समृद्ध देशों की तुलना में तीन प्रतिशत अधिक है।
- बचपन के स्टंटिंग के यानी अल्प-वृद्धि का प्रभाव वयस्कता में भी बना रहता है।
- इस रिपोर्ट के कई अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावों में से सबसे अहम् सुझाव यह है कि भारत में प्राइवेट स्कूलों का भी प्रदर्शन सार्वजनिक विद्यालयों जैसा ही है।
- यानी इस रिपोर्ट के बिंदु इस प्रचलित अवधारणा की विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है।
- ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन चौथाई और पाँचवीं कक्षा के आधे से ज्यादा छात्र दो अंकों का जोड़-घटाने वाला मामूली सवाल हल करने में सक्षम नहीं हैं।
- निम्न और मध्यम आय वाले 12 वैसे देशों की सूची में मालावी के बाद भारत दूसरे स्थान पर है जहाँ वैसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कक्षा 2 में हैं और किसी संक्षिप्त पाठ का एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिये, शिक्षा के जरिये गरीबी को खत्म करने और सबको समृद्ध बनाने के विचार को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता।

शिक्षा नीति में बदलाव आवश्यक क्यों?

- भारत के कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की हालत दयनीय है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे क्लासरूम की छत, शौचालय, बैठने की जगह आदि का आभाव है।
- शिक्षकों की कमी के कारण 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाना असम्भव प्रतीत हो रहा है।
- गौरतलब है कि 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक, गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (Teacher Eligibility Test – TET) उतीर्ण करना अनिवार्य है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 5 फीसदी शिक्षक ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण हैं।
- उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था एक - दूसरे के सामानांतर चल रही है: एक- अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तायुक्त शिक्षा, जबकि दूसरी- सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दोयम दर्जे की शिक्षा।

संभावित प्रश्न

विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2018 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की राह में मौजूद चुनौतियों को संबोधित किया गया है। इस कथन के सन्दर्भ में देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The World Development Report recently released by the World Bank, in 2018, has addressed the challenges facing the need for quality education. In the context of this statement discuss the shortcomings existing in the education system of the country and the appropriate solutions to overcome these shortcomings. (200 words)